SHRI PRAMOD MAHAJAN: Is the authority delegated to Jammu and Kashmir Statet

डा० संजय सिंह : सभापति महोदय, प्रमुख सवाल से संबंधित कई सवाल माननीय मंत्रीजी से पूछे गए हैं। जैसेकि काश्मीर घाटी की ला एण्ड आर्डर की स्थिति है, वह पूरे देश को मालूम है। दूर-संचार विभाग की एक अहमियत है, यह भी सब को मालूम है। पिछले अरसे वहां काफी कर्मचारी इस विभाग के मारे भी गए हैं। काफी लोगों की इसके बारे में चिंता है और पूरे सदन ने इस बारे में विचार व्यक्त किए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह संभव नहीं है कि भारतीय सेना जोकि वहां अपनी दूर-संचार व्यवस्था को देखती है तो क्या अपनी इस संचार विभाग की मैनिंग भारतीय सेना से कराई जा सकती है? दूसरे, वहां पर और ज्यादा लाइनों का आटोमेटिक एक्सचेंज स्टेंड-बाय में रखा जाय क्योंकि अगर इस तरह से कोई हादसा होता है तो हमारा दुनिया से संपर्क न कटे।

श्री राजेश पायलट : सभापति जी, जहां तक घाटी का सवाल माननीय सदस्य ने किया है, वहां पर जहां जहां हमें सेना की मदद मिली है, सेना की मदद भी ली है और हर जगह यह कोशिश की कि संचार घाटी का देश और विदेश से न कटे। आज भी हर जगह जहां जहां एस.टी.डी. डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर चल सकती है, वहां चलाने की कोशिश की है और फौज की वहां पर खुली मदद रहती है। जहां-जहां हम चाहते हैं वह बेचारे हमारी मदद करते हैं और उनके सहयोग से और पैरा-मिलिटरि फोर्स के सहयोग से ठीक चल रहा है। लेकिन, मैं विस्तार में यहां बता नहीं पाऊंगा कि वहां पर हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि यहाँ वह फैक्टर जो इतना मदद नहीं कर सकता। फौज के संचार इस तरह अच्छे चलते हैं, उनका अपना एक एरिया सेक्ल्यूडेड होता है, सभापति जी। उनका सब कुछ अपनी स जगह में होता है। हमारे जो ह्रैंज हैं ह सिविल एरियाज में हैं। वहां पर फौज भी इसलिए नहीं ले जा सकते कि वहां एक्सचेंज हमको फौज से ्रवाना है और फौज से चलवाना है। अभी फौज और पैरा-मिलिटरी दोनों को मिलाकर एक टीम स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखी है, जहां-जहां जिसकी जिस तरह के सहयोग की जरूरत होती है, उनके सहयोग से कर रहे हैं। लेकिन, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, जब घाटी का देश और विदेश से संचार न हो सके। ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी।

गुजरात और उत्तर प्रदेश में उपमंडल मुख्यालयों पर एस० टी० डी० की सुविधा

***402. श्री ईश दत्त यादव :**
श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात और उत्तर प्रदेश में कितने उपमंडल मुख्यालयों पर एस०टी०डी० की सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) इन राज्यों में शेष उपमंडल मुख्यालयों पर एस०टी०डी० की सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) गुजरात के 11 उप मंडलीय मुख्यालयों तथा उत्तर प्रदेश के 79 तहसील मुख्यालयों, जो उपमंडल मुख्यालयों का कार्य भी करते हैं, को 1-4-89 से 30-11-92 की अवधि के बीच एस०टी०डी० सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

(ख) सभी उपमंडल मुख्यालयों को मार्च, 1993 तक एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

---

*सभा में यह प्रश्न श्री ईश दत्त यादव द्वारा पूछा गया।

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर सभापति जी, इस युग में देश में और दुनियां में संबंध कायम रखने के लिये और आवश्यकता पड़ने पर तत्कालिक प्रभाव से कार्य करने के लिये दूरसंचार सेवायें अत्यावश्यक हो गई हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल के लोग, जिनकी संख्या अधिक है, इससे वंचित रहते हैं, उनको एस०टी०डी० सुविधायें उपलब्ध नहीं है । लेकिन मैं माननीय मंत्री श्री राजेश पायलट जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि मार्च, 1993 तक जो उपमंडल मुख्यालय हैं, तहसील मुख्यालय हैं, यहां एस०टी०डी० सुविधायें उपलब्ध करा देंगे । इसके लिये ये बधाई के पात्र हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, जो एक बहुत बड़ा प्रदेश है, इसमें अनेक टाउन हैं, कस्बे हैं बड़े, ब्लाक मुख्यालय हैं और अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं इनको एस० टी० डी० सुविधायें या टेलीफोन सेविधायें उपलब्ध नहीं हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इन ब्लाक स्तर के टाऊनों का, नगरों का भी सर्वे कराकर यहां पर भी टेलीफोन एक्सचेंज कायम करके उनको एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे और यदि ऐसा इनका प्रयास है तो यह कब तक पूरा कर देंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : सभापति जी, आज मैं सदस्य जी की बात से सहमत हूं कि आज ब्लाक लेवल ही नहीं, जहां कोई टलीफोन मांगता है, चाहे गांव में ही मांग रहा हो वहां जो है एस०टी०डी० पहले मांग रहा है । यह लोगों की एक जरूरत ही गयी है और मैंने हर बात में कहा है कि अब टेलीफोन कोई स्टेटस की बात नहीं रह गई है, टेलीफोन एक जरूरत हो गई है और आज के युग में संचार एक बहुत जरूरत की चीज हो गई है । लेकिन, उनके साथ साथ हमारे पास इतने साधन भी होने चाहियें, कि हम उन सबको एक साथ कर सकें । इन सबके लिये साधन की बहुत जरूरत होती है और आप सबको पता ही है कि मेरे साथी मनमोहन सिंह जी की जो हालत है, वह भी किसी से छिपी नहीं है, इनकी आर्थिक कमजोरियां भी हैं तो कहां से साधन इकट्ठा करें, वह भी आपके सामने समस्या सारी है । इन सबको रखते हुये हम लोगो ने एक नीति बनाई है कि हम तहसील हैडक्वार्टर और सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर की मार्च, 1993 तक कोशिश करें, जिससे हम सारे देश में इन इंपोर्टेंट जगहों पर एस० टी० डी० दे पायें । अब उनको अगर ब्लाक में भी आज आपसे कहें तो संभव नहीं हो पाये और जगह भी कहें, संभव नहीं हो पायेगा । यहां भी मैंने कहा – एफर्टस आर बीइंग मेड, क्योंकि मुझे दीख रहा है कितने रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, कितना शायद हम कर पायेंगे, कितना लगा पायेंगे, यह वक्त के ऊपर है । हमारे प्रयास है कि मार्च, 1993 तक तहसील हैडक्वार्टर और सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर पर यह एस०टी०डी० पहुंच जाय और गांव हमारा तहसील से जुड़ जाय तो कम से कम गांव तहसील से जुड़ जाए, तहसील देश और दुनियां से जुड़ जाए तो एक ही माध्यम हमारा चालू हो जाये । जो माननीय सदस्य ने ब्लाक और इंपोर्टेंट टाऊन्स की बात कही है, उसके बाद हम उस श्रेणी को लेकर शुरूआत कर सकते हैं ।

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर सभापति जी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-संचार की सेवायें हैं और जिनके बारे में माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है, तहसील मुख्यालयों पर, उप-मंडल मुख्यालयों पर यह संचार सेवायें पर्याप्त नहीं हैं और बराबर टेलीफोन एक्सचेंज खराब रहा करते हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना

चाहता हूं कि क्या उनको इस प्रकार की शिकायत मिली है कि ग्रामीण अंचलों में दूर-संचार सेवायें प्राय: ठप्प पड़ी रहती हैं ? उनको प्रभावी बनाने के लिये और सक्षम बनाने के लिये.....

THE CHAIRMAN; Please ask your quetisan.

श्री ईश दत्त यादव : : क्या इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने के लिये प्रयास करेंगे और जो तार पड़े हुये हैं, जो कट जाते हैं, चोरी हो जाते है, खराब रहते हैं, इनसे बचाव के लिये और सही व सक्षम सेवाओं के लिये केबिल डालकर के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राजेश पायलट : सभापति जी, इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजिस जहां-जहां, जिस तरीके से हमारे उत्पादन में आ रही है और जितना हम साधनों में सक्षम हैं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे देश में एकदम एलेक्ट्रानिक होना संभव नहीं है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर इलक्ट्रानिक एक्सचेंज लग सकते हैं, वहां पर हम लगायें।

जो माननीय सदस्य ने सवाल किया ग्रामीण क्षेत्र का, अगर आपने पढ़ा हो तो हमारे विभाग ने एक नई स्कीम दी है – ग्रुप डायलिंग स्कीम, जिसमें 20–25 किलोमीटर तक एक ग्रुप डायलिंग होगी, जो सुविधायें उसमें होंगी वे ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो जायेंगी। इसी लिये हम लोग ग्रुप डायलिंग स्कीम लेकर आये जिससे सारे देश में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सुविधायें हम-लोग दे सकें, इसी नीयत से हम लोगों ने नई स्कीम चालू की है। मुझे उम्मीद है कि कुछ इलाकों में यह हो गई है, अभी कुछ गांवों में भी एस०टी०डी० पहुंच गई है, जो तहसील हैडक्वार्टर नहीं है, लेकिन वे ग्रुप डायलिंग स्कीम के अन्दर आ जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा जब यह सारे देश में पूरी तरह से व्यापक रूप से लागू हो पायेगी क्योंकि इसके लिये साधनों की जरूरत है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साधन इकट्ठे करके हम इस स्कीम को जल्दी से जल्दी लागू करें।

MR. CHAIRMAN: Shri Solanki.

श्रीमती कमला सिन्हा : ओ हो, इधर भी सोलंकी हैं।

एक माननीय सदस्य : वे माधव हैं, ये गोपाल हैं।

SHRI S. JAIPAL REDDY: One Solanki will never speak in this House.

SHRI S. S. AHLUWALIA: When he speaks you will go out. That is why he is not speaking.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: 1 am very thankful to the hon. Minister for assuring provision of STD facilities in all the Sub-divisional headquarters in Gujarat.

At the same time I would like to say that there is a very sorry state of affairs in a particular area. Though it may not he relevant to this question. I would like to bring this to the notice of the hon. Minister. First 'I would like to ask him if there, is a procedure whereby a waiting list maintained is skipped over by a particular SDO and he is empowered to make an entry after that because of a political leader's telephone. Because of this a particular- person, is not provided a telephone connection according to his serial number. If not, then I would say that a was a sorry state of Affairs on the part of the Halol Exen This has been done here and the record is there. I think the Minister would call for the record also.

Now, I would like to ask my supple mentary. I would like to know how many Sub-divisional headquarters are surrounded by backward areas particularly in Pan-dhimahal, where there are four Talukas— San'trampur Jhalod Baria and Sabarkan-tha and also in Surat. I would like to know how many such, sub-divisions have

been left out in the provision of STD facilities and what efforts are being made for providing the same.

SHRI RAJESH PILOT: About the first part of the question, if the hon Member gives me the details, I will take action against the concernd officer. It is never allowed. Politics does not come in the functioning of the Government I may assure this to the hon. Member.

In regard *to* the part (b) of his ques tion, I really would not be able to give information districtwise, but I can give the information to the House. We have 19 district headquarters in Gujarat. All have STD facilities. We have 46 Sub-divisional Headquarters. Thirtynine have STD facility. We have 134 Talukas and Tehsils in Gujarat. Out of these 80 have been connected with STD facilities. The remaining 104 Tehsils are left with out STD facilities. In the next *2i* months, we will try to put in our *best* efforts so that by March, 1993 these places also will have STD facilities.

श्री राम नरेश यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी इस बात के लिये बहुत ही प्रयत्नशील हैं कि हम ग्राम पंचायतों तक टेलीफोन की सुविधायें पहुंचा दें और इस बात के लिये भी प्रयत्नशील हैं जैसा कि उत्तर में आया है कि हम मार्च, 93 के अन्त तक उत्तर प्रदेश के सभी तहसील हैडक्वार्टर्स तक एस०टी०डी० सुविधा पहुंचा देंगे । मैं इस संदर्भ में जानना चाहता हूं कि 1992–93 में उत्तर प्रदेश की कितनी तहसीलों में आपने एस०टी०डी० सुविधा देने का लक्ष्य रखा था और अब तक कितना पूरा हो गया है और क्या सचमुच में उसको मार्च, 93 तक पूरा कर सकेंगे ?

"बी" प्रश्न यह है कि महोदय, मैं अभी उस सिलसिले में मुबारकपुर गया था जबकि सांप्रदायिक दंगा फैला था । यह बड़ा कस्बा है जहां से बनारसी साड़ियां दूसरी जगहों पर जाती हैं । मैं वहां तीन जगह पर बैठा और वहां से दिल्ली का टैलीफोन करना चाहता था लेकिन टेलीफोन नहीं मिल पा रहा था, जबकि एस०टी०डी० सुविधा भी है । तो इस बात को ध्यान में रखते हुये जब आप एस०टी०डी० सुविधा तहसील हैडक्वार्टर्स तक पहुंचाने जा रहे हैं और जिसके लिये आप बधाई के पात्र हैं, किन्तु हम यह भी कहना चाहते हैं कि क्या आप सदन को आश्वस्त करेंगे कि एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराने के बाद भी जो उपभोक्ता है वह उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है । तो क्या यह उसका सही इस्तेमाल कर सकेगा, यह भी आप सदन को क्या अवगत करायेंगे ? यह बहुत आवश्यक है ।

श्री राजेश पायलट : सभापति जी, यह बात सही है कि क्वान्टिटी के साथ-साथ क्वालिटी भी रहनी चाहिये । यह बात मैं मानता हूं कि हम एस०टी०डी० सुविधा बढ़ाते रहें और वह काम नहीं करे तो कोई फायदा नहीं है । लेकिन माननीय सदस्य यह मानेंगे कि इतना बड़ा काम हमने एकदम शुरू किया तो उसमें टीथिंग प्रोब्लम्स हैं । अभी भी जहां-जहां एस०टी०डी० लगी है मैं यह नहीं कह सकता कि वह सौ फीसदी बिल्कुल परफेक्ट है उसमें कोई फाल्ट नहीं होगा । कभी कोई टेक्नीकल प्रोब्लम हो जाती है तो कभी कोई फाल्ट हो जाता है । मैं तमिलनाडु में खुद इनआग्युरेशन के लिये गया था । जब मैं वहां पहुंचा तो वह कहने लगे कि साहब, एक घंटा रुकिये । मैंने कहा कि क्या हो गया है ? उन्होंने बताया कि खबर आई है कि तार बीच में काट दिया गया है । अब पब्लिकली वह कहना नहीं चाहते थे कि तार किसने काट दिये हैं । एड-मिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम जल्दी से इसको ठीक करेंगे । तो ऐसी टीथिंग प्रोब्लम्स होंगी वह हमें सहन करनी हैं । The quality of service should noot go

हम उसको मेंटेन करें लटी अच्छी नहीं होगी तोकोई शन देने का फायदा नहीं है ।

दूसरा सवाल, माननीय सदस्य ने पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी लगी हैं । 294 ताल्लुकाज हैं, उसमें से 140 में लग गई हैं और अभी 154 में बाकी हैं और मार्च तक कोशिश करेंके कि इनमें भी लग जाये ।

श्री राम नरेश यादव : जो गति है उस गति के आधार पर नहीं लगता है कि मार्च, 93 तक यह सभी सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी । इसलिये इंश्योर करेंगे कि सचमुच में मार्च, 93 तक तहसील हैडक्वार्टर्स पर उपलब्ध हो जायेगी ।

श्री राजेश पायलट : मुझे तो आपका धक्का चाहिये कि करो, जितना होगा उतना करो । पहले क्यों निराश कर रहे हैं आप । लगा तो रहने दो मार्च तक ।

Mir. Chairman, Sir, I have been vary frank about the targtt and this is the target that we have taken up. If we do not take up a high target, we do not reach a high degree. I am keen that we must do it by March, 1993. We are putting pressure on the Department that we must achieve this target by March, 1993. I am trying my best to have it done by March, 1993.

श्रीमती सत्या बहिन : सभापति महोदय, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं । कि जब से यह आये हैं तब से संचार सेवाओं में उल्लेखनीय और क्रांतिकारी सुधार आया है इसके साथ ही... **(व्यवधान)** जी हां, आया है, यह आप महसूस करें ।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि पिछले दिनों आगरा में टेलीफोन एक्सचेंज में जो आग लगी थी उससे आगरा और उससे आसपास के जो कनेक्टेड जिले हैं, उनमें टेलीफोन की स०टी० डी० और नान-एस०टी०डी० दोनों ही सुविधायें प्रभावित हुई थी । अभी तक भी वह सुविधायें सामान्य नहीं हुई हैं । माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहती हूं कि उस एक्सचेंज से जितनी सेवायें प्रभावित हुई हैं–फिरोजाबाद, आगरा, एटा, मथुरा, मैनपुरी और इटावा यह जितने भी जिले हैं उनमें सामान्य सेवायें कब तक प्रारंभ हो जायेंगी? इनमें बहुत सारे औद्योगिक जिले भी आते हैं । यह मेरा सप्लीमेंटरी का भाग-अ है । दूसरा भाग में ये जानना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं जहां पर एस०टी०डी० सेवायें तो हैं लेकिन उसमें मशीनें पुरानी लगाई गई हैं जो अभी तक ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं । इसके लिये, उदाहरण के लिये मैं अपने जिले को बताना चाहती हूं कि ऐटा में मोदीनगर से.. **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: Please ask the question.

श्रीमती सत्या बहिन : : पार्ट ए है सर... **(व्यवधान)** वन सप्लीमेंटरी सर ।

MR. CHAIRMAN; Please ask it.

श्रीमती सत्या बहिन : मेरे ऐटा जिले में जो मोदीनगर से उतारी गई मशीन लगाई गई थी और मोदीनगर में ऐटा के लिये जो नयी मशीन आई थी उसको लगाया गया था जिसके कारण ऐटा है तो दूर संचार की एस० टी०डी० सर्विस ठीक से काम नहीं हो रहा है । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इस प्रकार के कितने केसेज हैं और उनमें नयी मशीनें कब तक लगाई जा सकेंगी ताकि वह सही मायनों में अपनी संचार सेवाओं से जुड़ सकें । मेरे दोनों सवालों का जवाब दीजिये माननीय मंत्री जी ।

श्री राजेश पायलट : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्या ने आगरा के बारे में डिटेल मांगी है । मुझे कुछ पता है... **(व्यवधान)**

श्री दिग्विजय सिंह : : आगरा के बारे में सोच-समझकर जवाब दें... **(व्यवधान)**

श्रीमती सत्या बहिन : आपसे पूछकर नहीं देंगे... **(व्यवधान)**

श्री दिग्विजय सिंह : मैं उनसे कह रहा हूं ।

श्री राजेश पायलट : मैं जनरल जवाब नहीं देना चाहता । मैं सही पता

करके वहां पर सुविधायें, एक्सचेंज में आग लगी थी और उससे नुकसान हुआ था । हमने उसी वक्त कुछ इंतजाम किये थे जिससे हमारी सुविधायें बराबर चलती रहें लेकिन पूरी खबर, सही खबर देने के लिये मैं माननीय सदस्या से कहूंगा कि मुझे टाइम दें, नोटिस दें जिससे मैं सही खबर दे सकूं कि यह हालत हमने वहां पर किस तरीके से ठीक की ।

श्रीमती सत्या बहिन : दूसरा सवाल बता दीजिये मान्यवर **(व्यवधान)** रिजेक्टेड मशीनें जो ऐटा में लगाई गई थीं . . . **(व्यवधान)**

Review of Indian Economy by the National; Council of Applied Edonomic Research

*403. SHRI V. NARAYANASAMY; Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the and year review of the Indian economy for the year 1992-93, done by the National Council of Applied Economic Research, shows that the exports are well below the target and Government expenditure will overshoot the budgeted amount; and

(b) if so, what fiscal measures government are taking for balancing the economy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR); (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) In a mid-year review of the Indian economy for the year 1992-93, the National Council of Applied Economic Research has observed that the current year's exports are below the targets and the overall Government expenditure may erceed the budgeted amount by the year-end.

During April-October, 1992, the growth rate of ovejall exports has shown a considerable improvement, Exports to general currency area (GCA) in dollar terms increased by 13.2 per cent in Apri-October, 1992 (over 1991) compared with an increase of 5.5 per cent, in April-October, 1991 (over 1990) and overall exports increased by 6.1 per .cent. during April-October, 1992 compared with a decline of 5.8 per cent-, during April-October, 1991.

As regard Government expenditure, the Government are determined to reduce gross fiscal deficit from 6.2 per cent, of GDP in 1991-92 to 5 per cent, of GDP in 1992-93. Total expenditure is being monitored regularly and Government are maintaining strict fiscal and monetary discipline.

SHRI V. NARAYANASAMY; Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has said that exports had increased by 6,1 per cent, during the period April-October, 1992.

The question of exports has to be considered, taking into account the imports being made. On this basis, the question of trade deficit has to be considered. Now, the Commerce Ministry appointed a Committee called the Sundaram Committee, to go into the question of credit facilities for the exporters. An interim report has been submitted by this Committee. They have suggested two things.

One measure Suggested by this Committee is, reduction in the interest rate for the people who are seeking credit facilities. Also, they have suggested thai credit sqeeze should not be imposed by the banks. But, Sir, the Finance Ministry scurtled it, Now, the imports are double that of exports, as on date, as per the figures.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister, what is the rate of increase in exports and imports, during the period April-October, 1992, in dollar terms? Secondly, there is a trade deficit. May I know whether there is a trade gap? If so, how are we going to manage It in the remaining period of three month?.